# ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा


पेजः 4

पानी की कमी से जूझ रहा है हर तीसरा बच्चा

रविवारीय, 31 अक्टूबर - 06नवंबर 2021 वर्ष- तीन, अंक -12, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

सभी पाठकों को ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी बधाइयां। कोरोना से मुक्त हो रहे विश्व में सर्वत्र लोग निरोग रहें, प्रकृति के साथ समन्वय रखते हुये सर्वत्र धन धान्य की संपूर्णता हो इस वर्ष की दीपावली सबों के जीवन से अंधकार दुख अवसाद मिटा कर खुशियों का प्रकाश और मिठास भर दे ग्रीन रिवोल्ट यही कामना करता है

# झारखंड में बनेगा ग्रीन फ्यूल इथेनॉल

**वरीय संवाददाता**

*विश्व के सारे देश जो पेट्रोलियम आयात पर निर्भर हैं वह सदैव वैकल्पिक ऊर्जा के लिये प्रयासरत रहते हैं। इसी का नतीजा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या से लेकर सौर ऊर्जा के उत्पादन की ओर विश्व कदम बढारहा है। लैटिन अमेरिकी देशों जैसे ब्राजील समेत विश्व भर में वाहनों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिला कर ईंधन के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। भारत में भी इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तो पेट्रोल के विकल्प के लिये विशेष रूप से लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 40 प्रतिशत लोग दोपहिया वाहनों का उपयोग अपने गंतव्य तक आने जाने के लिये करते हैं और पेट्रोल की बढती कीमत की सबसे ज्यादा मार इसी वर्ग पर पड़ती है। इथेनॉल जिसे ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं वह अनाजों, धान की भूंसी , गन्ने , चावल मकई जैसे उपज से बनायी जाती है और पेट्रोल में एक खास मात्रा में मिश्रण करने से ईंधन के खर्च में कमी आती है। अगर भारत में इथेनॉल का उत्पादन और वाहनों में इसका उपयोग सफल होता है तो आज आमजन पेट्रोल की कीमत और उससे पैदा हुये महंगाई से त्रस्त है उन्हें अवश्य ही राहत मिलगी। छत्तीसगढ में इथेनॉल उत्पादन पर वहां की सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है।*

अब झारखंड में भी इथेनॉल का उत्पादन किया जायेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड से इथेनॉल क्रय करने का करार किया है। सूचना के अनुसार केजी स्प्रीट्स, इनलैंड पावर, अंकुर बायोकेम, इस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल स्प्रीट्स लिमिटेड जैसी कंपनियों से एक दशक तक इथेनॉल खरीदने का अनुबंध केंद्र सरकार ने किया है। झारखंड में इथेनॉल का उत्पादन चावल, मकई और धान से किया जायेगा।कंपनियां झारखंड में इथेनॉल उत्पादन करने के लिये तैयारी कर रही हैं। झारखंड में धान की पर्याप्त उपज होती है, धान के अलावा धान के भूसी से भी इथेनॉल का उप्तादन होता है। इस लिये से इथेनॉल उत्पादन के लिये झारखंड में कच्चे माल की सदैव उपलब्धता रहेगी। राज्य में इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है इसका ड्राफ्ट तैयार है और जल्द ही इसका झारखंड में इथेनॉल उत्पादन के प्लांट लगाये जायेंगे।

**सब्सिडी :** झारखंड में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिये 10 करोड़ तक के सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। रामगढ , गोला में इनलैंड पावर 600 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट लगायेगा। जिससे 250 किलो लीटर से ज्यादा इथेनॉल प्रतिदिन उत्पादन होगा। जिसे पेट्रोलियम कंपनियां खरीदेगी। अनुमान है कि इन पांचों कंपनियों से प्रतिदिन 700 किलो लीटर इथेनॉल का उप्तादन होगा। इथेनॉल का उत्पादन और ईंधन के तौर पर उपयोग अगर सफल होता है तो देश में पेट्रोलियम पर हजारो करोड़ रूपये के खर्च की बचत होगी।

## पर्यावरण के लिये भी उपयोगी होगा इथेनॉल , इससे प्रदूषण कम फैलेगा

ईंधन में इथेनॉल का उपयोग सस्ता तो होगा ही साथ ही यह पर्यावरण के लिये बहुत ही उपयोगी होगा। इथेनॉल के इस्तेमाल से 35 फीसदी कम कार्बन मोनोऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है। इतना ही नहीं यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इथेनॉल के दहन से पेट्रोलियम की अपेक्षा कम प्रदूषण फैलता है। दोपहिया वाहनों की संख्या को अगर देखें तो इथेनॉल का प्रयोग उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन को पचास प्रतिशत तक घटा देगा वहीं चारपहिया वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण में भी तीस प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में एक परियोजना के उदघाटन के दौरान कहा था कि यदि राज्यों में एथेनॉल की फैक्ट्री शुरू की जाए तो राज्य की आर्थिक दशा में व्यापक सुधार आ सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार यदि बिहार झारखंड जैसे राज्यों में 100 ऐसी फैक्टियां लगाए तो केंद्र सरकार इसके लिए पूरी मदद करेगी और जितना एथेनॉल यहां बनेगा, उसे केंद्र सरकार खरीदेगी। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा होता है। भारतीय परिपेक्ष्य में देखा जाए तो इथेनॉल ऊर्जा का अक्षय स्त्रोत है क्योंकि भारत में गन्ने की फसल की कमी कभी नहीं हो सकती।

## विदेश निति तक बदल सकता है इथेनॉल

पेट्रोलियम आयात से भारत को आर्थिक और कुटनीतिक मोर्चे पर अक्सर मजबूर होना पड़ता है। पेट्रोलियम की आवश्यकता हमें अपने विदेश संबंधों में कई बार संकट में डालती रही है।तेल उत्पादक देशों के संघ ओपेक की कीमतों के सामने हम सदैव खुद को लाचार महसूस करते आये हैं। वर्तमान में तेल की बढती कीमत और उससे जनित महंगाई पेट्रोलियम पर हमारी विदेशों पर निर्भरता के कारण ही है। लॉक डाउन के समय पेट्रोल की कम मांग से हुये घाटे की पुर्ति के लिये ओपेक ने अभी कच्चे तेल की कीमत बढा रखी है।

पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता के कारण ही वैश्विक गुटबाजी में भारत को अपनी विदेश नीति और संबंधों को साधने में बहुत परेशानियां होती रही हैं।

# झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी तैयार

**मनोरंजन सिंह**

*झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के लागु हो जाने के बाद दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दस प्रतिशत या अधिकतम दस हजार रूपये तक की छूट मिलेगी। वहीं तीनपहिया वहनों में यह छूट तीस हजार तक हो सकती है। बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे बस ट्रक की खरीद पर 20 लाख तक की छूट मिल सकेगी।*

ग्रीन रिवोल्ट के 17 अक्टूबर 2021 के अंक में हमने यह सवाल उठाया था कि झारखंड में भी क्या इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर पड़ोसी राज्य उड़ीसा की तरह कोई नीति बनेगी ? यह संयोग और खुशी की बात है कि झारखंड सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इससे राज्य में पेट्रोल और डीजल पर हमारी निर्भरता घटेगी। यह पर्यावरण के लिये भी बहुत ही उपयोगी होगा। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट अब परिवहन विभाग के पास भेजा गया है जिसे कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किये जाने की उम्मीद है। इस पॉलिसी में आम लोगों के लिये वाहन खरीदी में कीमतों में छूट के अलावा रजिस्ट्रेशन एवं रोड टैक्स में भी छूट का प्रावधान है।

ग्राहकों को छूट के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने वाली कंपनियों के लिये भी सरकार ने राह आसान किया है। अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कोई कंपनी या बैट्री मैन्युफैक्चरर राज्य में प्लांट लगाते हैं तो सरकार निवेश का 25 प्रतिशत या 25 करोड़ तक सब्सिडी देगी।प्लांट के लिये जमीन खरीदी पर स्टांन और रजिस्ट्री शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया जायेगा। न्इस पॉलिसी के लागु होने के बाद दो साल के अंदर प्लांट लगाने वालों को सरकार पांच प्रतिशत का इंसेटीव भी देगी। बेशक झारखंड सरकार का यह कदम सराहनीय है।

# बीएयू के पीजी और पीएचडी के 31 छात्रों को सफलता मिली

संवाददाता

**कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ने नेट परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित किया**

**रांची :** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) - 2021 का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया है. बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 23 से 27 अगस्त, 2021 तक आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालयों से पीजी एवं पीएचडी धारक के कुल 2791 उम्मीदवारों ने 48 विषयों में नेट - 2021 परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये है। झारखण्ड राज्य के एकमात्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची के छात्रों को इस परीक्षा में पहलीबार बड़ी सफलता हासिल किया है. विवि के कुल 31 पीजी एवं पीएचडी धारक उम्मीदवारों ने 5 विषयों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्वालीफाई किया है.

विवि के कृषि संकाय अधीन सर्वाधिक 11 छात्र - छात्राएँ शस्य विज्ञान में सफल हुए है. इनमें पीजी डिग्री धारी छात्रों में पूजा कुमारी, राधे श्याम यादव, रुपेश कुमार, कीर्ति कुमुद एवं मनोज कुमार शामिल है. जबकि शस्य विज्ञान विषय में अध्ययनरत पीएचडी छात्रों में पियूष कुमार भार्गव, जया भारती, निकिता तिर्की, पियूष कुमार जयसवाल, सुलोचना एवं मीता कुमारी सफल हुए. आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विषय में पीजी छात्रों में जगदीश कुमार एवं अखिल कुमार तथा पीएचडी में अध्ययनरत प्रियंका कुमारी, प्रियंका एवं अंजनी कुमार को सफलता मिली है. कीट विज्ञान विषय में पीजी कोर्स में अध्ययनरत जक्कम चैतन्य रेड्डी, राखी पी एवं एम देवेंदर ने नेट पात्रता हासिल की है. वानिकी विषय में 7 छात्रों ने यह नेट परीक्षा को क्वालीफाई किया है. इनमें वानिकी संकाय से पीजी में डिग्री धारी छात्रों में अभय कुमार, विद्या सागर, नंदन मिश्र, ब्यूटी कुमारी , आलोक सिंह, श्रृष्टि एवं अंकित झा शामिल है. अभय कुमार संकाय में संविदा पर सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है।

पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विषय में पशु चिकित्सा संकाय से पीजी एवं पीएचडी में डिग्री धारी 5 लोगों में डॉ लवलीन खाखा,डॉ कुमारी नंदिता बेरा, डॉ सस्मिता बारीक़, डॉ राकेश कुमार एवं डॉ अलोक सिंह को सफलता मिली है. सभी संकाय में संविदा पर सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक/टीचिंग एसोसिएट के पद पर कार्यरत है. डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने बताया कि एएसआरबी नेट परीक्षा को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं / सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है. कृषि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर / व्याख्याता के रूप में प्रारंभिक भर्ती के लिए नेट एक शर्त है।

कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने विवि के 30 छात्रों द्वारा एएसआरबी नेट परीक्षा को क्वालीफाई करने पर प्रसन्नता एवं शुभकामना व्यक्त की है. डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव, डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद एवं डीन फॉरेस्ट्री डॉ एमएस मल्लिक सहित विवि के अनेकों प्राध्यापकों ने सफल छात्रों को बधाई दी है।

## सीएमडी सीसीएल ने 'आपातकालीन चिकित्सा ईकाई' का उदघाटन किया

**संवाददाता रांची** :सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने कांके रोड, रांची स्थित 'केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर' में नवनिर्मित ''आपातकालीन चिकित्सा ईकाई (ईएमयू)' का उदघाटन किया। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, सीवीओ एस.के. सिन्हा, सीएमएस सीसीएल डॉ डी.के.एल. चौहान, सीएमएस (प्रभारी), गांधीनगर डॉ. रत्नेश जैन सहित अन्य चिकित्सकगण एवं महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे। इस नवनिर्मित आपातकालीन वार्ड में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त 10 बेड का व्यवस्था किया गया है जो गंभीर मरीजों के लिए है। सभी बेड पर डाईरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई सहित एडवांस लाईफ सपार्ट सिस्टम है।

सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने कहा कि सीसीएल झारखण्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आपातकालीन वार्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

# सिल्क आधारित उत्पाद बनाने पर फोकस करे झारक्राफ्टःमुख्यमंत्री

संवाददातात रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के समक्ष झारखंड मंत्रालय स्थित सभा कक्ष में झारखंड सिल्क, टेक्सटाइल एंड हैंड-ीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (झा-रक्राफ्ट) के पदाधिकारियों द्वारा झारक्राफ्ट के बिजनेस मॉडल रिफॉर्म तथा ग्रोथ प्लान के संबंध में प्रेजेंटेशन रखी गई। पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि झारक्राफ्ट आने वाले दिनों में राज्य में निर्मित उत्पाद अथवा ब्रांड को बाजार में अधिक से अधिक बढ़ावा मिले इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर रहा है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पदाधिकारियों से कहा कि झारक्राफ्ट आउटडेटेड प्रोडक्ट न बनाएं बल्कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सिल्क आधारित उत्पाद बनाने पर अधिक फोकस करे। झारक्राफ्ट अपने उत्पाद का गुणवत्ता सुधारे तथा आधुनिक तरीके से प्रचार-प्रसार करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान अच्छे डिजाइनर रखकर उत्पाद को आकर्षक रूप दे। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि अन्य राज्यों के सिल्क से रिलेटेड संस्थानों में स्थापित संयंत्रों, तकनीकों तथा कंसेप्ट का स्टडी करें। मुख्यमंत्री ने कई और महत्वपूर्ण सुझाव पदाधिकारियों को दिए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिवपूजा सिंघल, एमडी झारक्राफ्ट आकांक्षा रंजन, निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह, निदेशक रेशम एवं हस्तकरघा दिव्यांशु झा उपस्थित थे।

# जी-20: विकसित देशों ने कोविड-19 वैक्सीन बांटने का आग्रह किया

*वैक्सीन के असमान वितरण से दुनिया में हर मिनट जा रही सात लोगों की जान, उपयोग में न लाने पर अगले कुछ सप्ताह में खराब हो जाएंगी ये वैक्सीन। जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रोम पहुंच रहे दुनिया के नेताओं को वैक्सीन के 'अनैतिक' वितरण से जान गंवाने वाले लाखों लोगों की चिंता सता रही है।*

गौरतलब है कि प्राचीन रोम सभ्यता में अमीर व शासक वर्ग, गरीब लोगों का शोषण करता था। उस साम्राज्य के गणतंत्र में बदलने, जिसके बाद गरीबों को भी अमीरों के तरह अधिकार मिलना सुनिश्चित हुआ, के काफी समय बाद रोम एक समकालीन वैश्विक पुनरावृत्ति का गवाह बनने जा रहा है। यह और बात है कि इस बार यह एक महामारी के साये में और लोकतांत्रिक परिदृश्य मे होगा। इस बार 'गरीब' वे देश हैं, जो को-विड-19 से जान बचाने वाली वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं, और 'अमीर व शासक'जी-20 के ताकतवर देश हैं। अमीर देशों के प्रमुख और उनके बुलाए मेहमान कल से दो दिन के लिए जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने को इटली की राजधानी रोम में जुटेंगे। इस बैठक में महामारी से उबरने, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर सौदे पर चर्चा होगी। हालांकि इस बार बैठक में जी-20 के नेताओं को महामारी के बाद पैदा हुई हेल्थ इमरजेंसी की चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा।

29 अक्टूबर को दुनिया के सौ से ज्यादा पूर्व प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों और नेताओं ने जी-20 के देशों से अपील की कि वे अपनी अतिरिक्त वैक्सीन को गरीब और विकासशील देशों के साथ साझा करें। उन्होंने यह अपील पत्र के जरिए इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से की है।पत्र में लिखा गया है कि अक्टूबर के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों, ब्रिटेन और कनाडा के पास ऐसी 240 मिलियन वैक्सीन का स्टॉक होगा, जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनमें से ज्यादातर वैक्सीन अगले कुछ सप्ताह में खराब हो जाएंगी। पत्र के मुताबिक, 'जब हर दिन कोविड-19 से दुनिया में दस हजार लोगों की जानें जा रही हों, और जिन्हें बचाया जा सकता है, तब इतनी मात्रा में वैक्सीन का बरबाद होना अनैतिक होगा। इस अपील के अनुसार, अगर इस बची हुई वैक्सीन को देशों के बीच समान रूप से बांटा जाए तो साल के अंत तक दुनिया की 40 फीसद आबादी को वैक्सीन दी जा सकती है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल के अंत तक दुनिया की 40 फीसद आबादी को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है।

भले ही आज की तारीख तक दुनिया भर में कोविड-19 की छह अरब वैक्सीन का प्रबंधन किया गया हो, लेकिन कम आय वाले देशों में महज दो फीसद आबादी को वैक्सीन मिल सकी है। नीतियों पर असर डालने वालों से अलग दुनिया के नेताओं पूर्व प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों का आकलन है कि अगर विकसित देशों के पास मौजूद अतिरिक्त वैक्सीन को गरीब और विकासशील देशों में बांट दिया जाए तो फरवरी 2022 तक इन देशों के 1.1 अरब लोगों को वैक्सीन मिल सकती है। इससे अगले साल बसंत तक दुनिया के 70 फीसद वयस्कों को वैक्सीन देने का विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकेगा।

डीटीई

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा



# हमारे त्यौहारों पर ही ये सब क्यों?

पिछले दो सालों से कोरोना महामारी ने पर्व त्यौहारों का उत्साह फीका कर रखा है। भारत में मॉनसून के समाप्ति के बाद जब हवा में ठंढक शुरू होती है और बारिश के भीगेपन से छुटकारा मिलना शुरू होता है तब यहां पर्व त्यौहारों का मौसम प्रारंभ होता है।

भारत पर्व त्यौहारों और उत्सवजीविता का देश है? यही इसकी अपार जीजीविषा का कारण भी है। भारत में आपदा, हिंसा, दुर्घटनायें, आतंकवादी हमले, महामारी और सीमाओं पर दुखद वाकये होते रहते हैं उसके बाद भी पर्व त्यौहारों के मौसम में रौनक, भीड़ और उत्साह में कोई कमी नहीं होती। देश विदेश के चिंतक विचारक भारतीयों के इस सोच की भर्त्सना कर सकते हैं, पर प्रत्येक दुख पीड़ा को भुला कर संघर्ष करना ,आगे देखना और भविष्य के प्रति आशान्वित रहना भारतीयों की शक्ति है।

पर्व त्यौहारों में अपनी परंपराओं को संपन्न करने पटाखे फोड़ने, खुशियां मनाने पर रोक की मांग अनुचित ही नहीं बल्कि देश की प्राणवायु को ही रोकने जैसा होगा।

दशहरा, दीपावली, छठ साथ ही खरीफ के फसल की कटाई का मौसम भी। मॉनसून , बाढ, आपदा और कई संकटों के बाद पर्व त्यौहारों और जाड़ो की शुरूआत देशवासियों के लिये कुछ महिनों की खुशी और उमंग लेकर आती है। आमजन इसमें अपने पिछले सारे दुखों को भुला कर खरीददारी करने, देव आराधना से लेकर खुशियों को खोजते हैं। ऐसा कोई हाल के कुछ वर्षों से नहीं बल्कि हजारों सालों के ऋतु परिवर्तन के साथ होते आया है। इधर कुछ सालों से दीपावली दशहरे और छठ के अवसर पर पर्यावरण बचाने, किसी और के आस्था पर चोट जैसे बहानों को लेकर सवाल उठाये जाते हैं। पटाखों से शोर और प्रदूषण, छठ से नदियों तालाबों को गंदा करने का आरोप लगा कर कोर्ट में याचिका डाली जाती है। महामारी को लेकर सावधानी जरूरी है, पर किसी पर्व त्यौहार की मूल प्रकृति पर ही रोक लगाने की मांग कहां तक जायज है।दीवाली बिना मिठाई और पटाखों के, छठ महापर्व बिना किसी जलाशय के कैसे मनेगा?एक आंकड़ा है कि दीवाली पर जितना प्रदूषण फैलता है उससे ज्यादा वायु प्रदूषण तो पराली जलाने से फैल रहा है।

कुछ पर्वों में पशु बलि से नदी नालों का पानी लाल हो जाता है, उस पर कभी किसी पर्यावरणविद् ने कोई याचिका नहीं डाली जब कि दीवाली और दशहरे में आम लोगों की खरीददारी से देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को पंख लग जाते हैं। ऐसे में दीपावली जैसे पर्व के खिलाफ कोर्ट में जाना सिर्फ एक दुर्भावना है और कुछ नहीं।

## तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से भारत में 25 गुना तक बढ़ जाएगा लू का कहर

यदि वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, तो भारत में 2036 से 2065 के बीच लू का कहर सामान्य से 25 गुना अधिक समय तक रहेगा। जी20 देशों पर जारी एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ता रहा तो सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। जिसके चलते 2036 से 2065 के बीच भारत में लू का कहर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अनुमान है कि इसके सामान्य से 25 गुना अधिक समय तक रहने की आशंका है।

इस रिपोर्ट को 30 से 31 अक्टूबर के बीच रोम में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले लॉन्च किया गया है। इस चर्चा के दौरान वैश्विक उत्सर्जन में कटौती के एजेंडे को आगे बढ़ाने की संभावना है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं के भाग लेने की संभावना है। गौरतलब है कि जी20 एक अंतर-सरकारी मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन को रोकथाम और सतत विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम करता है। यह रिपोर्ट यूरो-मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े 40 से अधिक वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा तैयार की गई है। यह शोध केंद्र इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के इतालवी केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में जलवायु परिवर्तन का जी20 के प्रत्येक सदस्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु में आ रहा बदलाव पहले ही जी20 देशों को प्रभावित कर रहा है। पिछले 20 वर्षों के दौरान सभी जी20 देशों में गर्मी से सम्बंधित मौतों में कम से कम 15 फीसदी की वृद्धि हुई है। जबकि जंगल में लगने वाली आग ने कनाडा से करीब डेढ़ गुना ज्यादा क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से लेकर साफ पानी की घटती उपलब्धता और डेंगू के कहर से लेकर भीषण गर्मी के कारण होने वाली मौतों तक जीवन का कोई ऐसा कोई पहलु नहीं होगा जो जी20 देशों में जलवायु परिवर्तन से अछूता रह जाएगा।

# सहराइ/बांदना परब :अपने पशुधन की पूजा -सेवा करते हैं किसान

अभी गांव घर में सोहराय/बांदना परब का बहुत ही चहल पहल चल रही है। कार्तिक महिना के पड़ने से ही लोग गांव घर में ढोल मांदल नगाड़ा करताल झुमका आदि बध्य यंत्र लेकर सहराय गीत गा रहे हैं। बांधना सहराय परब ऐसे तो कई समुदाय द्वारा मनाया जाता है लेकिन इसका सबसे अधिक रुझान एवं उत्साव कुड़मी समुदाय में देखा जाता है। यह परब मुख्य रूप से सबसे अधिक झारखंड, बंगाल उड़ीसा ,असम, आदि राज्यों में मनाया जाता है। परब के कुछ दिन पूर्व से ही महिलाएं घरों की मरम्मती जैसे मिट्टी, गोबर, रंग रोगन, चुना पोचड़ा आदि करती है।गांव की महिलाएं दूर-दूर से कई प्रकार की मिट्टी लाकर अपने घरों की रंगाई पुताई करती है एवं कई प्रकार की चित्राकंन कला का प्रदर्शन भी अपने मकानों के दीवारों में करती है, यानी देखा जाए तो चित्रकला शैली का विकास भी संभवत इसी सोहराइ पर्व से हुआ है।

कार्तिक माह के अमावस्या से 5, 7 या 9 दिन पूर्व से ही अपने घर की पशु जैसे गाय ,बैल, भैंस आदि की सींग में तेल दिया जाता है एवं घंटी ,घंटा या सजावट की वस्तुएं भी बैल भैंस को बांधा जाता है । तेल देउआ के अलावे सहराय परब मुख्य रूप से 5 दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है-

1) घाउआ/धउआ- अमावस्या के पहले दिन सभी किसान अपने अपने बैल भैंस को नदी, तालाब आदि जगहों में ले जाकर नहलाते है अर्थात धोया जाता है,इसलिए इस दिन को धउआ या कहीं-कहीं घाउआ के नाम से जाना जाता है।

2)गाय जागा/घिंगुआइनि- इस दिन पूरे गांव लोग घर आंगन की लिपाई करते है और शाम के समय गाँव के लोग ढोल नगाड़ा आदि वाद्य यंत्र लेकर अपने नया/पाहान के साथ गठइर अर्थात पूरे गांव के बैलों को जहां विश्राम हेतु कुछ समय के लिए इकट्ठा कर रखा जाता है उस जगह में जाकर गठ पूजा करते है। गांव के चरवाहे लोग जो गाय भैंस आदि वन जंगल में चराने के लिए जाता है वे लोग लकड़ी का पेइना काट के लाता है और गठ पूजा थान में बैठता है और नया/पाहान द्वारा पूजा सेंउरन

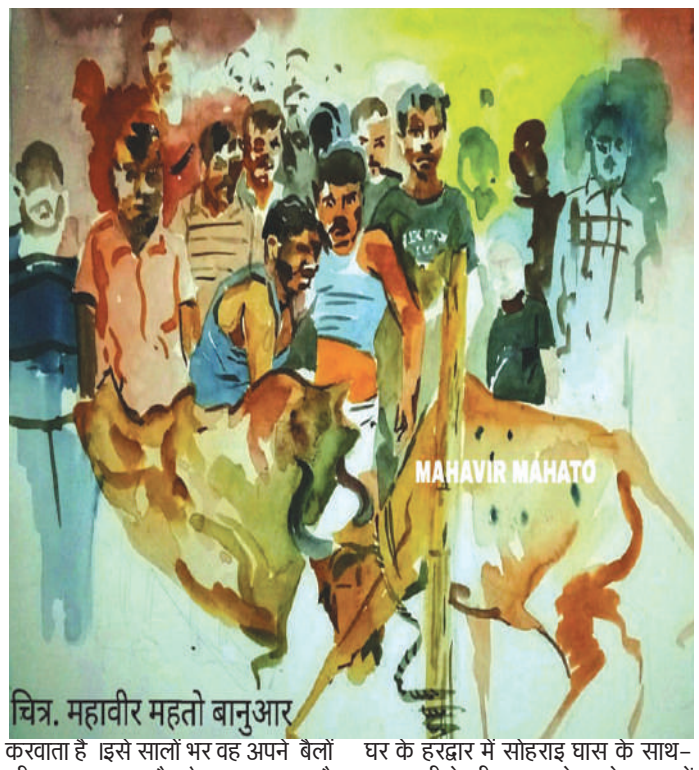

चित्र. महावीर महतो बानुआर

करवाता है ।इसे सालों भर वह अपने बैलों की रक्षा कर पाता है। ऐसा माना जाता है कि उस पइना को हाथ में रखने से सभी प्रकार के अपसकुन से वन जंगल आदि में रक्षा होती है । गांव के प्रत्येक घर जिसके यहां गाय दूध देती है वह अवश्य ही दूध लेकर पहुंचता है और उसी दूध मे आरूआ चावल, गुड़ आदि देकर प्रसाद तैयार कर चढ़ाया जाता है। इसे "जुड़ी" कहा जाता है। गठ पूजा में मुर्गा की बलि भी दी जाती है । इसमें सफेद मुर्गा का विशेष महत्व होता है ।इसके पश्चात लोग अपने अपने पैइना उठाते हैं और पाहान/नया गठ के बीचो बीच एक अंडा रखता है फिर लोग बैलों को लाते हैं और उस गठ पूजा थान से गीत गाकर के बैलों को पार करते हैं इसी क्रम में जिसके घर का बैल अंडा फोड़ता है वह नया को कंधे करके नाच गान के साथ अहिरा गीत गाकर घर लाता है फिर धोती / गमछा आदि देकर सम्मानित करता है। शाम के समय प्रत्येक घर में कांची दियारी देने का विधान भी है ।इसमें घर के हरद्वार में सोहराइ घास के साथ-साथ गुड़ी के दीया जला के प्रत्येक द्वार में रखा जाता है। इसे करने से घर में गाय गुरु की सगुन होती हैं और उसके घर में इसकी वृद्धि दिनोंदिन होती है। दीया में प्रयोग गुड़ी को जला के पिठा बनाया जाता है और फिर घर के सभी लोग इस पीठा को थोड़ा-थोड़ा खाते हैं।इसके बाद बच्चे शाम को इंजर पिंजर का खेल खेलते हैं। हर घर के बच्चे पटसन को जलाकर इधर-उधर दौड़ते हैं और खेलते है। रात को घिंगुआइनि शुरू होती है सबसे पहले गांव के नया के घर से शुरुआत होती है फिर क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक घर में गाय जागरण हेतु यह काम क्रम से किया जाता है। घिंगुआइन घर में प्रवेश करने पर विशेष तौर पर बैल भैंस को गुड़ी का छिंटा देकर जगाया जाता है इसके बाद गहाइल घर में घी का दीया जलाया जाता है फिर तेल देने के पश्चात घास खिलाया जाता है।घिंगुआइन प्रायः गांव के लोग ही होते हैं और हर घर में विभिन्न प्रकार के सहराइ गीत गाते हैं। इसमें चांचर गीत की काफी लोकप्रियता है। अमावस्या के रात भर गाय जागरण के पश्चात घिंगुआइन सब पूरे गांव घूमते हैं और जाहलिबुला गित गाते हुए चलते हैं इस बीच कुड़मी समुदाय में एक विशेष नेग होता है इसमें छोटे बच्चों को घिंगुआइन के आगे लेटाया जाता है और सभी घिंगुआइन उसे पैर की बड़ा अंगूठा छुआ के पार होता है । ऐसा माना जाता है की इस जोग में यदि बच्चों को पैर की अंगूठा छुआ के लांगकर पार होता है तो बच्चा में किसी भी प्रकार की पेट आदि से संबंधित बीमारी नहीं होती है और बच्चा ताकतवर एवं अपने पुरखों के नियम का अनुसरन कर चलता है।

3) गरइआ पुजा- गरइआ पुजा बांधना परब का एक अभिन्न भाग है। इस दिन घर का एक पुरुष एवं एक महिला उपवास करके रहते हैं ।घर आंगन की साफ सफाई एवं लीपा पोती के पश्चात महिला नहा धोकर आती है फिर चावल का गुड़ी ढेकी से कुटती है और फिर अलग से चूल्हा बनाकर शुद्ध दूध में सान कर धि से पीठा छांकती हैं । किसान घर के खेती-बाड़ी में प्रयोग होने वाले औजार जैसे हल जुआँइट,राकसा मइर आदि को धोकर भूत पीड़ा में रखता है ।इसके बाद पुरुष नहा धोकर आता है और गोरइया पूजा के लिए तैयार होता है। भूत पीड़ा में पूजा सेंउरन के पश्चात गरइआ पूजा की जाती है। गरइआ का शाब्दिक अर्थ है गअ + रइआ अर्थात गाय -गुरु की रक्षा करने वाले देवता। नौ देवता भुता जिसकी पुजा वह गहाइल में करता है, जिसमें मुख्य रूप से बुढ़ाबाबा , माहामात्र के साथ साथ गराम देउता,धरमराइ,गसाञराइ, बिसाइचड़ि, बड़अपाहाड़ जाहिरमात्र एवं बाघुत।

इन नौ देवा भूता की पूजा के लिए गुड़ी से नौ घर बनाया जाता है फिर इन्हें सेंउरन कर फुल जल देकर घी का छांका हुआ पीठा चढ़ाया जाता है,फिर मुर्गा की बलि दी जाती है। फुल में सालुक फूल की प्रधानता होती है। इसके पश्चात चावल का गुड़ी को घोल कर चौक पूरा जाता है ।इसमें सबसे पहले ,पहला चौक के शीर्ष भाग में गोबर रखा जाता है ।उसके ऊपर एक सोहराय घास देकर सिंदूर का टीका दिया जाता है एवं एक बछिया से उसे लंगवाया जाता है। शाम के समय घर के सभी गाय , बैल भैंस को तेल दिया जाता है और एक गाय जो सबसे बड़ी होती है जिससे श्री गाय कहा जाता है और सबसे बड़ा बैल जिसे श्री बरद कहा जाता है को पैर धो कर सिंदूर देकर माड़इड़ पहनाया जाता है और एक खाम खुंटा में बांधा जाता है (माड़इड़ जो धान शिश का बना होता है ) ।इसका मतलब होता है की हम जिस अनाज को जिन गाय गरु की बदौलत उपजायें हैं उसे सब से पहले उसी के सिर पर चढ़ा कर ईमान को जगा रहे हैं । फिर महिला उसे चुमान बंदन करती है। इसके बाद निंगछा जाता है। इस दिन हल, जुआँइट,राकसा गाड़ी आदि की भी पूजा की जाती है क्योंकि इसके सहयोग से ही खेत में अनाज उगाया गया है इसीलिए इसकी भी पूजा सेंउरन जाती है।

4) बरदखुँटा- इस दिन घर आंगन की लीपापोती कर पुनः कुल्ही से लेकर संपूर्ण आंगन में चौक पूरा जाता है एवं घर के सभी गाय ,बैल ,भैंस के लिए माड़इर बनाया जाता है ।इस दिन भी पैर धोकर सभी गाय ,बैल ,भैंस आदि को तेल सिंदूर देकर चुमान बंधन किया जाता है फिर उसे खूंटा जाता है और सोहराय गीत गा गा ढोल नगाड़ा मादइर के साथ चमड़ा लेकर उसे आत्मरक्षा का गुरुर सिखाया जाता है ताकि वह जंगल में हिंसक जानवरों से अपनी और अपने दल का रक्षा कर सकें। इस दिन प्रत्येक घर में अच्छे अच्छे पकवान एवं खाना बनता है ।लोग रिझ रंग में मदमस्त होकर नाचते गाते और उत्सव मनाते हैं। इस दिन प्रत्येक घर के चौखट में सिंदूर देने का भी रिवाज है।

5) गुड़ि बाँदना- बरद खुंटा के दूसरे दिन को गुड़ी बांधना के नाम से जाना जाता है ।इस दिन फेटाइन बछिया को जो लंबे समय से गर्भधारण नहीं कर पाती है उससे खूंटा जाता है और विभिन्न प्रकार के गीत गाकर उसके गुड़ी यानी गर्भाशय को बांधन किया जाता है जिसे वह जल्दी गर्भधारण कर सके। ऐसी पुरानी मान्यताएं है ।इस प्रकार हर्षोल्लास के साथ 5 दिन तक सोहराइ/ बंदना परब मनाया जाता है।

**सहराइ जोहार**
**(हरे किसन हिंदइआर दा की कलम से)**

# कृषि आंकड़ों के डिजिटलीकरण से पहले जन-जागरूकता जरूरी

**सुरिंदर सूद**

भारतीय कृषि के डिजिटलीकरण की कवायद में कॉर्पोरेट जगत को भी जोडऩे की सरकार की हालिया पहल से इस मुहिम को तेजी मिलने की उम्मीद जगी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र के उत्पादन से लेकर खपत तक की मूल्य शृंखला में शामिल विभिन्न पक्षों को इस लायक बनाना है कि वे अपने पेशेवर एवं कारोबारी मसलों से जुड़े सूचना-आधारित निर्णय कर सकें। इस कवायद के केंद्र में विराजमान किसानों की डिजिटल पहुंच हो सकेगी जिससे वे समय पर परिस्थिति के मुताबिक समस्या के समाधान के तरीके जान सकें। उन्हें इस बारे में भी सुझाव मिल सकेंगे कि कौन-सी फसलें और उनकी कौन-सी किस्में उगाई जाएं और उपज की बढिय़ा कीमत पाने के लिए उन्हें कब और कहां पर बेचा जाए? इससे संबंधित प्रायोगिक परियोजना चलाने के लिए हाल ही में कृषि मंत्रालय ने पांच कारोबारी समूहों के साथ औपचारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रायोगिक परियोजना एक साल के लिए कुछ खास इलाकों में चलाई जाएंगी। अगर उपयोगी पाए गए तो फिर दूसरे इलाकों में भी इनका विस्तार किया जाएगा।

वर्ष 2021-25 की अवधि के लिए डिजिटल कृषि मिशन भी शुरू किया गया है जिसमें कृत्रिम मेधा, ब्लॉकचेन डेटा सुरक्षा, सुदूर संवेदी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), ड्रोन एवं रोबोट जैसी नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इन कंपनियों में रिलायंस समूह की

आईटी इकाई जियो, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी सिस्को, आईटीसी, अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी एनसीडीईएक्स की आईटी शाखा एनईएमएल और ताजा उपज की आपूर्ति करने वाली कंपनी निन्जाकार्ट शामिल है।

करीब 5.5 करोड़ किसानों के कृषि-संबंधी आंकड़ों का पहले ही डिजिटलीकरण हो चुका है। इस साल के अंत तक यह आंकड़ा 10 करोड़ किसानों तक पहुंच जाने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इस डेटाबेस को किसानों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा जिससे एक राष्ट्रीय डेटा संसाधन बनाया जा सके। हरेक किसान को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने में ये डेटा बहुत काम आएगा। किसान आईडी की मदद से किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले नकद लाभ एवं दूसरे तरह के समर्थन एवं सेवाओं के लिए चिह्नित करने में आसानी होगी। जियो एवं उसकी सहयोगी इकाइयों ने पहले ही 'जियोकृषि' प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो मृदा परीक्षण एवं जल उपलब्धता के आधार पर फसल उत्पादकों को परामर्श देने के साथ सीधे कृषि वैज्ञानिकों से किसानों का संवाद स्थापित करने में भी मदद करता है। नई परियोजना के तहत महाराष्ट्र के जालना एवं नाशिक जिलों में इस तरह की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसी तरह अपनी ई-चौपाल नेटवर्क के लिए मशहूर कंपनी आईटीसी ने स्थान-केंद्रित डिजिटल फसल परामर्श सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है और इसके साथ किसानों को खेतों में इन सुझावों पर अमल के लिए जरूरी मदद भी मुहैया कराएगी। आईटीसी ने मध्य प्रदेश के सीहोर एवं विदिशा जिलों के चुनिंदा गांवों में गेहूं की खेती के समय अपनी सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा है। सिस्को ने अपनी साझेदार क्वांटेला के साथ मिलकर डिजिटल कृषि ढांचा खड़ा किया है और उन्नत कृषि तरीकों से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए इसे दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम मेधा टूल से जोड़ा भी है। कंपनी हरियाणा के कैथल और मध्य प्रदेश के मुरैना में इसी तरह का डिजिटल नेटवर्क खड़ा करने में मदद करेगी।

एनईएमएल किसानों की समस्याओं के समाधान तलाशने के लिए सक्षम करने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करेगी। बाजारों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक-दूसरे से जोडऩे, मांग बढ़ाने, वित्तीय संबद्धता और डेटा प्रबंधन में संलग्न एनईएमएल उपज की आवक, कीमतों के रुझान और गोदामों की मौजूदगी के बारे में सूचनाएं इक_ा करेगी। वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर, कर्नाटक के दावणगेरे और महाराष्ट्र के नाशिक जिलों के किसानों को यह तकनीकी मदद मुहैया कराएगी। निन्जाकार्ट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं इंदौर और गुजरात के आणंद में एक कृषि-बाजार प्लेटफॉर्म के विकास के लिए काम करेगी। इसके लिए फसल कटाई के बाद उपज को बाजार तक पहुंचाने से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी।

हालांकि ऐसा लगता है कि कृषि संगठनों के एक तबके को ये प्रस्ताव कुछ खास अच्छे नहीं लगे हैं। खासकर वामपंथी रुझान वाले कृषि संगठनों को नए प्रस्ताव ज्यादा पसंद नहीं आए हैं। पहली नजर में किसानों के लिए फायदेमंद नजर आ रहे इन प्रस्तावों पर उनकी आपत्ति किसानों से जुड़े आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच होने को लेकर है। उनकी आपत्तियां किसानों का निजी ब्योरा सार्वजनिक करने, बदहाली में रखे भूमि दस्तावेजों को गलत तरीके से पेश करने और कृषि के कॉर्पोरेट चंगुल में फंसने की आशंकाओं से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि ऐसा होने से असली खेतिहर किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ होने लगेगा। हालांकि सरकार ने इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा है कि किसानों से संबंधित डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों के बारे में निजी जानकारियों क ो किसी भी संगठन के साथ साझा नहीं किया जाएगा। कृषि संबंधित आंकड़ों के संकलन, संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए एक अलग नीति भी बनाई जा रही है। कृषि मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर इस नीति का खाका बनाने में लगा हुआ है।

बहरहाल, कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों को लेकर किसानों के बीच व्याप्त तमाम आशंकाओं को देखते हुए कृषि मंत्रालय के लिए यही मुफीद होगा कि कृषि आंकड़ों को डिजिटल करने से संबंधित किसानों की चिंताओं को पहले दूर किया जाए। मौजूदा वक्त की दरकार यही है कि इसके बारे में सुव्यवस्थित जागरूकता अभियान चलाया जाए। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के व्यापक विरोध को देखते हुए यह अनिवार्य है कि उनकी कड़ी प्रतिक्रिया को शांत किया जाए।

## सितंबर 2022 तक खत्म हो सकती है कोविड-19 महामारी, डब्ल्यूएचओ ने बताया तरीका

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जब तक सब जगह से कोरोनावायरस संक्रमण खत्म नहीं होता, तब तक कोविड-19 महामारी को नहीं रोका जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से बचाने वाली वैक्सीन, जांच और उपचार में असमानता का मुकाबला करने के लिए लगभग 2.34 अरब डॉलर की जरूरत है। इस पैसे से ऐसे देशों की मदद की जाएगी, जो अत्यधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए बकायदा एक रणनीति बनाई है और सक्षम देशों से गुहार लगाई है कि वे आगे आकर पैसे का इंतजाम करें। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले दो माह के दौरान एक बार फिर से दुनिया भर में कोविड-19 के केसों में वृद्धि हो रही है।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोविड-19 महामारी का खात्मा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से चलाए जा रहे वैश्विक कार्यक्रम ञ्च एसीटी (द अक्सेस टू कोविड टूल्स) ऐक्सैलेरेटर काफी महत्व रखता है। इससे दुनिया भर में सम्भावित 50 लाख मौतों और लगभग 5.3 ट्रिलियन डॉलर के बराबर वैश्विक आर्थिक नुकसान को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस कार्यक्रम के अत्याधिक जोखिम झेल रहे देशों की मदद की जाएगी। साथ ही, ऐसे उपकरण व संसाधनों का इंतजाम किया जाएगा, ताकि सितंबर 2022 तक कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर खत्म किया जा सके।

## 50% तक कम कमाते हैं घर से काम करने वाले कामगार: आईएलओ

एजेंसियां: हाल ही में आईएलओ द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट 'वर्किंग फ्रॉम होम: फ्रॉम इनविसिबिलिटी टू डीसेंट वर्क' से पता चला है कि भारत में घर से काम करने वाले कामगार औसत से 50 फीसदी तक कम कमाते हैं। इसी तरह अर्जेंटीना और मेक्सिको में भी घर से काम करने वालों की आय, बाहर काम करने वालों की तुलना में 50 फीसदी तक कम होती है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका में 25 फीसदी, अमेरिका में 22 और यू के में घर से काम करने वालों की आय औसत से 13 फीसदी तक कम होती है। ऐसा सिर्फ निचले स्तर के कामगारों के साथ ही नहीं हुआ है बल्कि उच्च और कुशल कामगारों पर भी इसका असर पड़ा है।

सिर्फ आय ही नहीं घर से काम करने वालों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम भी ज्यादा है। इन लोगों को अन्य कामगारों की तुलना में प्रशिक्षण मिलने की सम्भावना भी कम है, ऐसे में इनके कैरियर और भविष्य की संभावनाओं पर भी असर पड़ रहा है।

# किसी भी हरित क्षेत्र को वन मान कर हो उसका रख रखाव

**एन .के. मुरली**

***पुराने हो चुके भारतीय वन अधिनियम में संशोधन काफी समय से लंबित थे, खासतौर पर सन 1996 के बाद से जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के जरिये वनों तथा उनके संचालन की अवधारणा की बुनियाद को ही बदल दिया था।***

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी हरित क्षेत्र 'वन' शब्द को चरितार्थ करता हो उसे वन माना जाना चाहिए और उस-का उसी अनुसार रखरखाव होना चाहिए। इसके साथ ही ज्यादातर हराभरा भूभाग वन मान लिया गया, भले ही उसका स्वामित्व किसी के पास हो। ऐसे में उस जमीन के किसी भी तरह के इस्तेमाल के पहले वन अधिकारियों की मंजूरी जरूरी हो गई। रेलवे तथा सड़क जैसे स-ार्वजनिक विभागों को भी उस स्थिति में वन विभाग से इजाजत लेनी जरूरी हो गई जब उनकी खाली पड़ी जमीन में पेड़ पौधे उग आए हों। सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं

को भी इस समय खपाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता और आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ती। ऐसे में वन मंत्रालय ने मौजूदा वन कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करके अच्छा काम किया। हालांकि यह कवायद लंबी खिंच रही है। सन 2017 और 2019 में ऐसे दो प्रयास विफल रहे क्योंकि प्रस्तावित बदलावों को लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी। अब पर्यावरण मंत्रालय एक नए और व्यापक संशोधन वाले नोट के साथ आगे आया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया है ताकि विशिष्ट अंशधारक तथा राज्य सरकारें इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। इस नए पाठ में पिछले मसौदों के कई विवादित प्रावधानों को हटा दिया गया है तथा आवश्यक बदलावों के साथ यह इस कानून में बदलाव का आधार तैयार करता है। विवादों की तादाद कम करने के लिए इसमें जहां छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड समाप्त करने की बात है, वहीं बड़े अपराधों के लिए अपेक्षाकृत भारी भरकम जुर्माने तथा वन संरक्षण के लिए कड़े मानकों की बात कही गई है। इससे भी अहम बात यह है कि इसमें 'प्राचीन जंगल' की नई अवधारणा शामिल की गई है। यह वह इलाका होगा जहां किसी भी हालत में किसी तरह की गैर कृषि गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। तेल एवं प्राकृतिक गैस खनन की इजाजत भी तभी होगी जब इसके लिए वन भूमि से बाहर जमीन में छिद्र किया जाए और इस दौरान भूमिगत जल स्त्रोतों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। हालांकि यह प्रावधान विवादास्पद हो सकता है क्योंकि इस तकनीक की व्यवहार्यता को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है।

दूसरी ओर, नए मसौदे में वन क्षेत्र को लेकर कुछ अहम और जरूरत आधारित सुधारों को शामिल करने की बात कही गई है। ये सुधार निजी भूमि पर भी वानिकी गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इनके मुताबिक निजी भूमि पर फसल उगाने, उसे लाने ले जाने और उसका कारोबार करने की राह में आने वाली अधिकांश बाधाओं को दूर किया जाना है। परंतु इसके साथ ही नए मसौदे में कृषि वानिकी पर जोर नहीं दिया गया है जबकि इसमें ग्रामीण इलाकों में हरित क्षेत्र का विस्तार करने तथा किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने की काफी संभावना है। निजी भूमि पर पौधरोपण और कृषि को बढ़ावा देना अब अनिवार्य हो गया है क्योंकि सरकार और समुदाय के स्तर पर नए वन तैयार करने के लिए जमीन का अभाव है। 33 फीसदी हिस्से को वनाच्छादित बनाने तथा जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते में स्वयं के लिए तय 2.5 से 3 अरब टन क्षमता की कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन सिंक (वह व्यवस्था जहां उत्सर्जन से अधिक कार्बन खपत होती है) करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी अहम है।

हमें वनों के विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन कायम करना होगा। इसके लिए निजी और सार्वजनिक का तालमेल आवश्यक है।

## ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगेंगे

रांची :यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए निम्न ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगेंगे ।

ट्रेन संख्या 08605 राउरकेला – जयनगर स्पेशल ट्रेन में दिनांक 30/10/2021, दिनांक 02/11/2021, दिनांक 04/11/2021 और दिनांक 06/11/2021 को द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त कोच तथा वातानुकूलित 3– टियर का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा ।

## सीसीएल के सेवानिवृत कर्मियों को भावभीनी विदाई

रांची :सी.सी.एल. के निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव सहित 76 कर्मी सेवानिवृत हुए सम्मान समारोह में श्रीवास्तव सहित सभी सेवानिवृत कर्मियों को भावभीनी विदाई

सी.सी.एल. के निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव तथा सी.सी.एल., मुख्यालय विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों सर्वश्री सुरेन्द्र नायक, कार्यालय अधीक्षक, 'ए-1', एसडी एवं सीएसआर विभाग; दीपक कुमार बोस, कार्यालय अधीक्षक, 'ए-1', वाशरी कंस्ट्रक्शन विभाग; अर्जून कुमार राय, ड्राईवर कम मेकनिक, ई एण्ड टी विभाग तथा केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर से एतवारी कुमारी देवी, मेट्रन 'ए-1'; जोगेश्वर भुइंया, वार्ड बॉय, 'ग्रेड-एच' को आज सीसीएल परिवार की ओर से सीसीएल मुख्यालय में ''सम्मान समारोह'' का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई। पूरे सीसीएल से अक्टूबर माह में 76 सेवानिवृत कर्मियों को भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये सम्मान समारोह का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई।

# केसीसी बना किसानों के लिए वरदान

### किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से मिल रहा ऋण

रांची :किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ऋण का उपयोग कर किसान खेती के लिए बीज, खाद व जरूरी उपकरण खरीद रहे हैं। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है।

मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन ने निर्देश दिया था कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़ा जाए और इसका लाभ उन्हें मिले। जिसका प्रतिफल है कि अक्टूबर 2021 के पहले सप्ताह तक राज्य के 20,1687 लाभुकों के ऋण के लिए 68,516 लाख रुपए की स्वीकृत दी गई थी। कृषि के साथ मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यहां कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है कि किस तरह केसीसी राज्य के किसानों की खेती में सहायक सिद्ध हुआ है।

### आसानी से मिला ऋण, सब्जियों की खेती कर मुनाफा कमाया

अनु उरांव कांके के पिठौरिया स्थित कुम्हरिया गांव के निवासी हैं। इनका कहना हैं कि किसानों की बड़ी समस्या खेती के लिए पूंजी जुटाना होता है, क्योंकि पूंजी नहीं होने से वे समय पर खाद, बीज आदि नहीं खरीद पाते हैं। अनु उरांव ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में जाने से उन्हें केसीसी के बारे में जानकारी मिली। जिसके बाद केसीसी के लिए आवेदन दिया। केसीसी के जरिए मिले ऋण का उपयोग उन्होंने ड्रीप एरिगेशन व खेती से जुड़े अन्य कार्यों के लिए किया। ढाई एकड़ में खीरा, टमाटर, पत्तागोभी की फसल लगायी थी। अनु बताते हैं पॉली हाउस में सब्जी की खेती करने का भी फायदा मिला। वे अब अगले सीजन के लिए तरबूज की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं। अनु बताते हैं कि सब्जियों की खेती में प्रति एकड़ 80 से 90 हजार रुपये तक की लागत आती है। सब्जियों की साल भर में तीन फसल ले पाते हैं। सारे खर्च को निकालने के बाद तकरीबन डेढ़ लाख रुपये तक की बचत हो जाती है।अनु उरांव कुम्हरिया एग्रो कांके फॉमर्स कंपनी लिमिटेड से भी जुड़े हैं। स्थानीय किसानों के इस संगठन में कुम्हरिया और आसपास के गांवों के 150 किसान जुड़े हैं। लगभग 50 किसान तो कुम्हरिया गांव से ही है। केसीसी के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आप अपनी जरूरत भर का ऋण ले सकते हैं। वह भी काफी कम ब्याज दर पर।

### केसीसी से मिले ऋण से गेंहू और सरसों की खेती

प्रकाश भगत गुमला जिले के घाघरा प्र-खंड स्थित चुन्दरी नवांटोली गांव के निवासी है। उन्हें पंचायत के मुखिया से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से होनेवाले फायदे के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि पहले तो साहूकारों से कृषि कार्य के लिए ऋण लेना पड़ता था, पर केसीसी से यह फायदा हुआ कि साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि उनके पास सात एकड़ कृषि भूमि है। जिसमें से आधे हिस्से पर वे धान की खेती करते हैं और आधे में गेहूं की। केसीसी से उन्होंने 46,000 रुपये का ऋण लिया था। इसका उपयोग उन्होंने गेंहू और सरसों की खेती में लगाया। खेती के नये तरीके अपनाने और मेहनत करने की वजह से अच्छी फसल हुई। प्रकाश बताते हैं कि सारे खर्च निकालने के बाद उन्हें 40,000 रुपये का लाभ हुआ। वे अपना केसीसी का ऋण चुका चुके हैं और अब गेंहू की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं।

### आलू और गेंहू की खेती कर रहे खूंटी के नरेश महतो

खूंटी के मान्हो सिलादोन गांव के निवासी नरेश महतो को एक महीने पहले ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के बारे में जानकारी मिली। योजना के बारे में जानकर उन्होंने ऋण के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरा कर आवेदन किया। नरेश महतो को 50,000 रुपये का ऋण मिला। नरेश के पास कृषि के लिए लगभग पांच एकड़ भूमि है। हालांकि इसमें से कुछ भूमि पर खेती नहीं हो पाती। नरेश ने 40 डिसमिल भूमि पर आलू की खेती की है। इसके अलावा वे एक एकड़ भूमि पर गेंहू की फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। नरेश महतो ने कहा कि केसीसी काफी अच्छी योजना है। इससे किसानों को खेती कार्य के लिए खाद, बीज व जुताई आदि करने में काफी सहूलियत हो रही है।

मुख्यमंत्री के आदेश पर युद्ध स्तर पर किसानों को केसीसी मुहैया कराया जा रहा है । कृषक मित्र, एटीएम, बीटीएम एवं वीएलडब्लू टोला-टोला घूम कर किसानों से केसीसी फॉर्म भरवा रहे हैं। फलस्वरूप इस वर्ष अप्रत्याशित रूप से सबसे अधिक केसीसी आवेदन भरवाए गए हैं। यदि किसी त्रुटि के कारण बैंक कुछ आवेदनों को अस्वीकार करते हैं, तो कृषि विभाग के कर्मचारी इन आवेदनों को शुद्ध कर पुनः बैंक में जमा भी करा रहे हैं।

# सामाजिक परिवर्तन युवाओं से ही संभव:मुख्यमंत्री

संवाददाता

रांची : विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड विधान सभा में आयोजित दो दिवसीय प्रथम झारखंड छात्र संसद-2021 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। प्रथम झारखंड छात्र संसद-2021 में राज्य के विभिन्न जिलों के विश्वविद्यालयों से चयनित 24 छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं।

### प्रथम झारखंड छात्र संसद-2021 में शामिल हुए मुख्यमंत्री

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका की बेहतर जानकारी होना सभी के लिए महत्वपूर्ण है चाहे वे राजनीतिज्ञ, शिक्षक या सामान्य व्यक्ति ही क्यों न हो। मैं समझता हूं कि मजबूत समाज तथा मजबूत देश वही होता है जहां राजनीतिक, सामाजिक और संसदीय चेतनाएं व्यापक होती हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित लोकसभा सदन एवं विभिन्न राज्यों के विधानसभा के द्वारा राज्य एवं देश को दिशा दी जाती है। समाज के विभिन्न वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए यहीं से कानून बनाई जाती है और इसी कानून के रास्ते विकास का पहिया आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मामलों पर लोगों के अपने अपने विचार होते हैं यही कारण है कि विधान सभा सदन में भी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही सक्रिय रहते हैं। दोनों पक्ष मिलकर राज्य को नई दिशा देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रथम झारखंड छात्र संसद-2021 के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप सभी नौजवान यहां विधायी प्रक्रियाओं को समझेंगे। आप यहां पर जो चीजें जानेंगे । मुझे विश्वास है कि आप अपने आस-पास के क्षेत्र में लोगों के साथ साझा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी सभी तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। समाज की आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक विकास के लिए सभी की जिम्मेदारी सुनिश्चित है लेकिन वर्तमान समय में उस जिम्मेदारी को व्यवहार में उपयोग करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सदन की स्वस्थ परंपरा को गढ़ने का प्रयास करेंगे जो आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी। सामाजिक परिवर्तन युवाओं के माध्यम से ही संभव है।

# सभी मतदाता अपना पहचान पत्र ऐप पर ऑनलाइन अपडेट करेः के. रवि कुमार

### पूरे नवंबर विशेष ड्राइव, मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान
### मतदाता जागरूकता का पोस्टर व वीडियो लांच

**रांचीः** झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र को निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर लें। इसे अपने मोबाइल फोन पर आसानी से किया जा सकता है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे, वे प्रज्ञा केंद्र से इसकी सुविधा ले सकते हैं। ऐप पर हर समस्या का समाधान है। वहीं आयोग के विशेष शिविर में जाकर भी वे नाम में त्रुटि, पता, फोटो आदि को अपडेट करा सकते हैं। साथ ही एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो चुके सभी लोग मतदाता सूची में नाम जरूर दर्ज कराएं। इसके लिए सभी कॉलेजों के प्राचार्य से पत्राचार कर सहयोग की अपील की गई है।

इस कार्य के लिए आयोग एक नवंबर से 30 नवंबर तक नागरिकों से दावा एवं आपत्ति प्राप्त करेगा। उसके लिए 20, 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन होगा। वहीं 24 नवंबर को दिव्यांग जनों के लिए विशेष कैंप लगेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि अच्छा चुनाव के लिए अच्छा मतदाता सूची जरूरी है।

## डालमिया सीमेंट बोकारो में स्थापित करेगा संयंत्र

संवाददाता

रांची : झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर मीट में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड एवं उद्योग विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा किए गए एमओयू के अनुसार सीमेंट प्लांट की स्थापनाके लिये डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को एमओयू के अंतर्गत भूमि का तय समय सीमा के अंतर्गत आवंटन ,अधिपत्य एवं आवंटित भूखंड का लीज डीड प्राधिकार के स्तर से संपन्न किया गया है। इसके तहत करीब 577 करोड़ का निवेश सुनिश्चित हुआ। संयंत्र की स्थापना से प्रति वर्ष 2.0 मिलियन टन का उत्पादन होगा। सीमेंट संयंत्र की स्थापना का कार्य नवंबर 2021 में प्रारंभ होगा। संयंत्र का निर्माण एक वर्ष के अंदर पूर्ण होने की संभावना जताई गई है। राज्य सरकार ने संयंत्र स्थापना के लिए कंपनी को बोकारो जिला के बालीडीह में 16 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया है।

**577 करोड़ का निवेश हुआ सुनिश्चित**

## दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस का पालन

कोलकाता में 31 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में अपने मुख्यालय गार्डनरीच में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया ।अर्चना जोशी, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टुकड़ी द्वारा प्रस्तुत औपचारिक परेड की सलामी ली और अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करने और देशवासियों के बीच इस संदेश को प्रचार-प्रसार करने का संकल्प लिया।

अर्चना जोशी, ने इस अवसर पर आरपीएफ कर्मियों द्वारा आयोजित मोटर साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस के संदेश का प्रसार करने के लिए आज सुबह दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय, गार्डनरीच में आयोजित "रन फॉर यूनिटी" को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों, दक्षिण पूर्व रेलवे के खिलाड़ी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यों ने भाग लिया।

# सीसीएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह लाइव पेन्टींग वर्कशॉप का आयोजन

संवाददाता

रांची : मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, सीसीएल एस.के. सिन्हा के कुशल नेतत्व में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" के अंतर्गत सीसीएल कर्मियों के साथ-साथ आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त भारत हेतु जागरूक, प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए सतर्कता विभाग, सीसीएल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । आज इसी क्रम में इस वर्ष के थीम ''स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता'' पर आधारित सीसीएल मुख्यालय प्रांगण में ''लाईव पेन्टींग वर्कशॉप'आयोजित की गई । युवा कालाकारों ने कार्यशाला में आजादी का अमृत महोत्सव एवं सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता का संदेश से ओत-प्रोत अपने रंगीन और रचनात्मक पेंटिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की शोभा बढाई एवं अपने कला का प्रदर्शन किया।

पेन्टींग वर्कशॉप का उद्घाटन सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने किया। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता पदाधिकारी एस.के. सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, कर्मी एवं अन्य उपस्थित थे। सीएमडी ने कलाकारों का उत्साहवर्द्धन करते हुये कहा कि 'पेंटिंग' कर्मियों के साथ-साथ आमजन को जागरूक करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हम सभी को दैनिक जीवन में भी सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों का आत्मसात करना होगा।

पेन्टींग वर्कशॉप में झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, संस्थानों (रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, हजारीबाग, बचरा, पिपरवार) के लगभग 25 वरिष्ठ प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समन्वयन वरीय प्रबंधक (कार्मिक) आलोक गुप्ता ने किया।

कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन के साथ-साथ स्टॉल (आशा, कोशिश) का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संत जेवियर्स कालेज, रांची के कलाकारो द्वारा नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया जिसे उपस्थित सभी लोगों ने खूब सराहा। एक्आईएसएस, बीआईटी मेसरा, रांची यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

# सीएमपीडीआई में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया

**संवाददाता रांची :** सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर सीएमपीडीआई में ''राष्ट्रीय एकता दिवस'' समारोह का आयोजन किया गया। ''राष्ट्रीय एकता दिवस'' के अवसर पर आज सीएमपीडीआई के मुख्य भवन के समक्ष संस्थान के निदेशक श्री ए0के0 राणा ने सीएमपीडीआई के कर्मियों को एकता प्रतिज्ञा दिलायी। इससे पूर्व निदेशकद्वय श्री ए0के0 राणा एवं श्री एस0के0 गोमास्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर मार्ल्यापण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर संस्थान के महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में सीएमपीडीआई परिवार के लोग उपस्थित थे।

प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह के पश्चात सीएमपीडीआई के निदेशकद्वय श्री ए0के0 राणा एवं श्री एस0के0 गोमास्ता के नेतृत्व में ''रन फॉर यूनिटी'' का आयोजन किया गया जिसमें सीएमपीडीआई (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय संस्थान-3 के अधिकारी एवं कर्मचारीगण सम्मिलित हुए।

# इथेनॉल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता

*मुरलीधर*

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते कच्चे तेल के दाम और उसके हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ते दबाव को देखते हुए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। पहले सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में बीस फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा था।

पिछले दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने अब इसे घटाकर 2025 कर दिया है। सरकार की मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत इसे कालांतर में सौ फीसदी एथेनॉल से चलने वाले वाहनों के रूप में लक्ष्य हासिल किया जाये। दरअसल, सरकार की सोच रही है कि अपनी आर्थिक संप्रभुता के लिये हमें नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ानी होगी। इसमें बैटरी से जुड़ी प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जहां वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट है, वहीं वर्ष 2030 तक इसे 450 गीगावॉट किया जायेगा। सरकारी की प्राथमिकताओं का प्रतिफल यह है कि वर्ष 2014 में जहां 38 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा जाता था, वह अब 320 करोड़ लीटर खरीदा जा रहा है। बीते साल तेल बाजार की

कंपनियों ने 21 हजार करोड़ रुपये का एथेनॉल खरीदा। केंद्र का दावा है कि पिछले सात सालों में हमारी अक्षय ऊर्जा की क्षमता में 250 फीसदी वृद्धि हुई है। फलतः आज भारत अक्षय ऊर्जा के मामले में शीर्ष पांच देशों में शामिल है। निस्संदेह, 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा अपरिहार्य बन गई है। यही वजह है कि वर्ष 2014 तक पेट्रोल में जहां 1.5 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता था, वह अब 8.5 फीसदी हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से गन्ना किसानों के खाते में। इसी कड़ी में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी ई-100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे में लॉन्च किया गया है। वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा में पिछले छह साल में 15 गुना वृद्धि की बात सरकार कर रही है।

वक्त की मांग है कि एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को चीनी उत्पादक राज्यों के इतर अन्य राज्यों में भी विस्तार दिया जाये। तभी देश के विभिन्न राज्यों में सड़े अनाज व खेती से निकले कचरे आधारित संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। करनाल जनपद में एथेनॉल संयंत्र में धान की पराली का उपयोग किया जायेगा, जो पराली प्रबंधन की समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नियामक ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी करके पेट्रोल में 'हरित ईंधन' एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिसमें धान के भूसे के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई है, जिससे भविष्य में इसकी मांग व उपयोग में वृद्धि की उम्मीदें जगी हैं। फिलहाल करनाल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एथेनॉल प्लांट में धान की भूसी का उपयोग होगा। हालांकि, इसके लिये खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रसंस्करण अप्रैल, 2022 में आरंभ होगा, जिसमें किसानों की पराली प्रबंधन में होने वाले खर्च को बचाने में मदद की जायेगी। दरअसल, रबी की फसल के लिये सीमित समय होने के कारण किसान इसे खेतों में जला देते हैं। अब पराली प्रबंधन में इस नई पहल से मदद मिलेगी। अच्छी बात यह है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार पंजाब, हरियाणा व उ.प्र. में पराली जलाने में इस साल कमी देखी गई है। सर्दियां शुरू होने के साथ ही दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आती थी। फिर उसे दुरुस्त करने के उपाय किये जाते थे। कोविड महामारी, जिसने हमारे श्वसनतंत्र को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ने हमें स्वच्छ वातावरण की जरूरत को बताया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी एक एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की योजना है, जिसके लिये आसपास के राज्यों से पराली खरीदी जा सकेगी। वहीं मुक्तसर के रहरियांवाली गांव में ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी मदद के धान की भूसी को गांठों में बदलने, गौशालाओं में इस्तेमाल करने तथा उन्हें राजस्थान व गुजरात को आपूर्ति करने की प्रेरक पहल की है। निस्संदेह, व्यक्तिगत जागरूकता भी महत्वपूर्ण है।

# अक्टूबर में हिमाचल में बर्फबारी सेब बागवानों को भारी नुकसान

रोहित पराशर

हिमाचल प्रदेश में 3000 मीटर से अधिक ऊंचे इलाकों में सेब बागवानों पर दोहरी मार पड़ी है। यहां सेब से लदे पेड़ों का नुकसान हुआ है। आमतौर पर अक्टूबर माह में बहुत कम बर्फबारी होती है, लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों से मौसम ज्यादा अनियमित हो गया है। इस बार भी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हुई भारी बर्फबारी से किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। यह कहना है कि किन्नौर जिले के गांव शलखर के सेब बागवान गौरव कुमार का। 3100 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव की आर्थिकी पूरी तरह सेब बागवानी और बेमौसमी सब्जियों की खेती पर निर्भर है। गौरव कुमार ने डाउन टू अर्थ को बताया कि 17-18 अक्टूबर को हुई बर्फबारी से किसानों की आर्थिकी पर दोहरा असर पड़ा है। दो दिनों तक हुई भारी बर्फबारी से किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और लाहौल के बागवानों की न सिर्फ तैयार फसल खराब हुई है, बल्कि इससे सेब के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है।बर्फबारी के कारण किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई इलाकों में सेब के पौधे जड़ों समेत उखड़ गए हैं। 9 अक्टूबर को भी हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी दर्ज की गई है।

अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के बाद हिमाचल के कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के उंचाई वाले क्षेत्रों में तीन बार बर्फबारी हो चुकी है। मौसम विभाग के आंकडों के अनुसार 15 से 22 अक्टूबर तक लाहौल स्पीति, कुल्लु, किन्नौर, सिरमौर, षिमला और सोलन में बहुत अधिक बारिश दर्ज की गई है।18 अक्टूबर को हिमाचल में 16.7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। वहीं 25 अक्टूबर को लाहौल के मडग्रां में 15.4 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। जिसे किन्नौर और लाहौल के लोग सामान्य घटना नहीं मान रहे हैं।हालांकि मौसम विभाग के निदेशक डॉ सुरेंद्र पाल कहते हैं कि अधिक ऊंचाई वोले क्षेत्रों में बर्फबारी सामान्य घटना है और यह होती रहती है। डॉ सुरेंद्र का कहना है कि आगामी दिनों में लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले के उंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं।कृषि विभाग के किन्नौर जिला के उप निदेशक आत्मा बलवीर ठाकुर का कहना है कि किन्नौर के निचले क्षेत्रों में सेब की फसल खत्म हो चुकी है, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बागवानों का नुकसान हुआ है।उन्होंने बताया कि फसल ले चुके किसानों के लिए ये बर्फबारी लाभदायक है और इससे बागवानों का लाभ मिलेगा। इससे बागवानों के चिलिंग आवर पूरे होंगे।

समय से पहले हुई भारी बर्फबारी की वजह से न सिर्फ बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुआ है, बल्कि इससे पर्यटन क्षेत्र पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। अचानक हुई बर्फबारी की वजह से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों पर्यटक फंस गए थे। वहीं ट्रैकिंग पर गए 8 लोगों की मौत भी खराब मौसम में फंस जाने की वजह से पिछले 10 दिनों में हो चुकी है। एसडीएम काजा महेंद्र प्रताप बताते हैं कि मौसम के अचानक खराब हो जाने की वजह से स्पीति के विभिन्न स्थानों में पर्यटक फंस गए थे। जिन्हें प्रशासन, पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों के सहयोग से निकाला गया है। यह पहला मौका नहीं है, जब अक्टूबर माह में हुई अचानक भारी बर्फबारी के कारण किसान-बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो। इससे तीन साल पहले भी लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी की वजह लाहौल और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के बागवानों की सेब की फसलों और सेब को पौधों को भारी नुकसान पहुंचा था। जिसका खामियाजा बागवान अभी तक कम फसल के रूप में भुगत रहे हैं।

# कॉप - 26: गंभीर रूप से पानी की कमी से जूझ रहा है हर तीसरा बच्चा

***संयुक्त राष्ट्र संघों ने जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रेड कोड किया, जो समग्र विकास की अवधारणा पर सवाल खड़े करता है। ग्लासगो में यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के जलवायु शिखर सम्मेलन (कॉप-26) से दो दिन पहले, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों ने देशों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में पानी को एक अभिन्न अंग बनाने की अपील जारी की है।***

विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), आईएफएडी, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, यूएनईसीई और (जीडब्ल्यूपी) जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने देशों के प्रमुखों को संबोधित एक पत्र में कहा गया है, "जलवायु परिवर्तन के कारण पानी पर पड़ रहे असर पर बात करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि पानी की वजह से लोग ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी प्रभावित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने यूनिसेफ की एक पूर्व रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि पानी की कमी की वजह से दुनिया के एक तिहाई से अधिक बच्चों की आबादी प्रभावित हो रही है। "यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020" में इस बात पर जोर दिया गया है कि जलवायु का पानी से सीधा संबंध है और इसे जलवायु परिवर्तन (पेरिस समझौता), सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और आपदा के जोखिम कम करने (सेंडाई फ्रेमवर्क) में सहयोग ओर समन्वय की जरूरत है।

सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य "सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना" है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तरह जल क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने मांग की है कि सभी देशों को जलवायु परिवर्तन को रोकने या अनुकूल बनाने के साथ-साथ पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। जैसा कि सतत विकास लक्ष्य 6 में भी कहा गया है, जिस पर सभी राष्ट्र सहमत भी है। सतत विकास लक्ष्य 6 में पानी की उपलब्धता, टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना और सभी के लिए स्वच्छ पानी की बात कही गई है। एजेंसियों ने कहा है कि सभी देशों को जलवायु एजेंडा और पानी को एकीकृत करना चाहिए और अपने अपने देशों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बनाए गए जलवायु एजेंडा में पानी को भी शामिल करना चाहिए। इसे सात जरूरी प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए।

चूंकि देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम संबंधी आपदाएं बहुत आ रही हैं। इसलिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसे मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे की कमी आपदाओं से होने वाले नुकसान को बढ़ा देती हैं। एजेंसियों के इस पत्र में सुझाव दिया गया है कि ऐसे ठोस इंतजाम किए जाएं, जिससे पानी से संबंधित आपदाओं के बारे में समय से चेतावनी जारी की जा सके और इसे सात प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए।

**डीटीई**

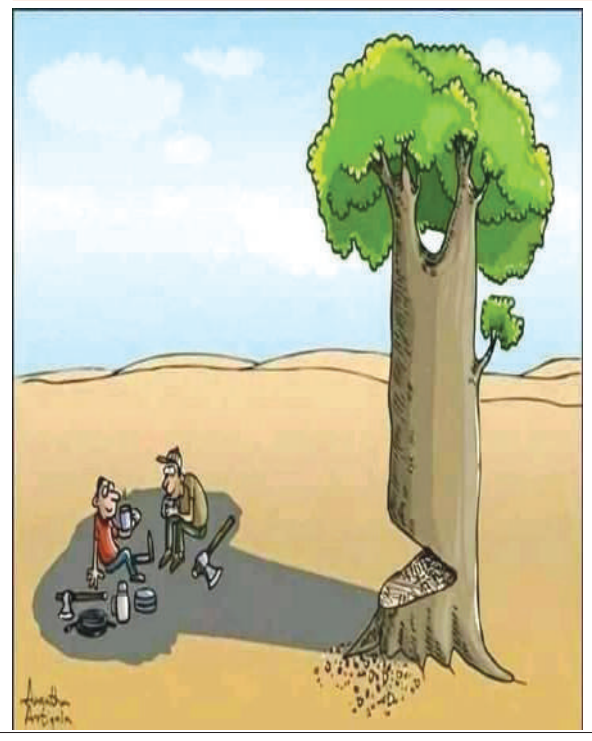

## कॉप-26: तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से भारत में 25 गुना तक बढ़ जाएगा लू का कहर

एजेंसियां

यदि वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, तो भारत में 2036 से 2065 के बीच लू का कहर सामान्य से 25 गुना अधिक समय तक रहेगा। जी20 देशों पर जारी एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ता रहा तो सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। जिसके चलते 2036 से 2065 के बीच भारत में लू का कहर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अनुमान है कि इसके सामान्य से 25 गुना अधिक समय तक रहने की आशंका है।

इस रिपोर्ट को 30 से 31 अक्टूबर के बीच रोम में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले लॉन्च किया गया है। इस चर्चा के दौरान वैश्विक उत्सर्जन में कटौती के एजेंडे को आगे बढ़ाने की संभावना है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं के भाग लेने की संभावना है। गौरतलब है कि जी20 एक अंतर-सरकारी मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन को रोकथाम और सतत विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम करता है। यह रिपोर्ट यूरो-मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़े 40 से अधिक वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा तैयार की गई है। यह शोध केंद्र इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के इतालवी केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में जलवायु परिवर्तन का जी20 के प्रत्येक सदस्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

## 2020 में सबसे अधिक 33,164 दिहाड़ी मजदूरों ने की आत्महत्या

एजेंसियां

***राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, खेती किसानी से जुड़े लोगों द्वारा आत्महत्याओं के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई है***

साल 2020 में रोजाना कमाने वाले यानी दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की आत्महत्या में वृद्धि हुई। 2019 के मुकाबले बेरोजगारों द्वारा आत्महत्या में भी वृद्धि हुई, हालांकि किसानों की आत्महत्या में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की, जो 2019 के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक थी। 2019 में 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र (19,909) में दर्ज की गईं, इसके बाद तमिलनाडु में 16,883 आत्महत्याएं, मध्य प्रदेश में 14,578 आत्महत्याएं, पश्चिम बंगाल में 13,103 आत्महत्याएं और कर्नाटक में 12,259 आत्महत्याएं हुईं। कुल आत्महत्याओं की दृष्टि से देखा जाए तो इन पांच राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई। 2020 पूरी तरह से कोविड-19 महामारी वर्ष रहा और साल के लगभग नौ महीने लॉकडाउन रहा। बावजूद इसके आत्महत्याओं में कमी की बजाय वृद्धि हुई। पिछले कुछ सालों से सबसे अधिक आत्महत्याएं दिहाड़ी कर रहे हैं। 2020 में भी यही ट्रेंड देखा गया, बल्कि पिछले सालों के मुकाबले इसमें और वृद्धि हुई। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में सबसे अधिक आत्महत्याएं (24.6 प्रतिशत) दिहाड़ी मजदूरों ने की, जबकि साल 2019 में यह प्रतिशत 23.4 था। 2020 में 33,164 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, जबकि 2019 में 29,092 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। 2020 में 10,677 ऐसे लोगों ने आत्महत्या की, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े थे। यानी कि 5,579 किसानों और 5,098 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की। जबकि 2019 में 5,957 किसानों और 4,324 खेतिहर मजदूरों (कुल 10,281) ने आत्महत्या की।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पिछले पांच साल की रिपोर्ट्स का आकलन किया गया तो पाया कि 2015 में सबसे अधिक (19.1 प्रतिशत) स्वरोजगार करने वाले लोगों ने आत्महत्या की थी। जबकि दूसरे नंबर पर दैनिक वेतनभोगी मजदूर (17.8 प्रतिशत) आत्महत्या की। जबकि तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग थे। इस साल 23,799 दैनिक वेतनभोगियों और खेती व्यवसाय से जुड़े 12,602 लोगों ने आत्महत्या की।

2016 में भी आत्महत्या करने वालों में रोजाना कमाने वाले मजदूर दूसरे नंबर पर थे। हालांकि उनका प्रतिशत बढ़ा था। कुल में से 19.2 प्रतिशत आत्महत्या करने वालों में दिहाड़ी मजदूर ही थे। पहले नंबर पर अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग थे। इस साल 25,159 दैनिक वेतनभोगी मजदूरों और खेती व्यवसाय से जुड़े 11,379 लोगों ने आत्महत्या की। 2017 में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों ने सबसे अधिक आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में कुल के मुकाबले इस साल 22.1 प्रतिशत दैनिक वेतनभोगी मजदूर थे। इस साल 28,737 मजदूरों ने आत्महत्या की, जबकि खेती किसानी से जुड़े लोगों की संख्या में कमी आई और उनकी संख्या 10,655 रही।

2018 में आत्महत्या करने वालों में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों का प्रतिशत 22.4 रहा। इस 9.4 प्रतिशत बेरोजगारों ने आत्महत्या की, जबकि खेती किसानी से जुड़े लोगों की संख्या 7.7 प्रतिशत रही। संख्या की दृष्टि से बात करें तो 30124 दैनिक वेतनभोगी और खेती किसानी से जुड़े 10,349 लोगों ने आत्महत्या की। दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की अगर बात करें तो सबसे अधिक तमिलनाडु में 6495, मध्य प्रदेश में 4945, महाराष्ट्र में 4176, तेलंगाना में 3831, गुजरात में 2754, आंध्र प्रदेश में 2501, केरल में 2496, कर्नाटक में 2373, छत्तीसगढ़ में 1964, राजस्थान में 1128, पश्चिम बंगाल में 895, असम में 789, पंजाब में 749, हरियाणा में 721, त्रिपुरा में 338, ओडिशा में 274, उत्तर प्रदेश में 245, उत्तराखंड में 119, हिमाचल प्रदेश में 142, बिहार में केवल 69, मेघालय में 66 दैनिक मजदूरी करने वालों ने आत्महत्या की।

## कॉप-26: काफी नहीं है राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, पैसे की कमी से प्रगति में रुकावट

***यूएनएफसीसीसी ने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की***

**एजेंसियां :** ग्लासगो में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे संक्षेप में कॉप-26 के नाम से जाना जाता है,अब शुरू हो गया है। उससे पहले जारी दो रिपोर्टों में बताया गया है कि दुनिया का तापमान बढ़ने से रोकने के लिए तैयार किए पेरिस समझौते का लक्ष्य हासिल करने में तमाम देशों के प्रयास नाकाफी है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे आर्थिक उपाय भी निराशाजनक हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) की एक दिन पहले राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। रिपोर्ट परिष्कृत एनडीसी का मूल्यांकन करती है। इसका पहला हिस्सा इसी साल फरवरी में प्रकाशित हुआ था और पूरी रिपोर्ट पिछले महीने तैयार हुई थी। नई रिपोर्ट, जो सितंबर की रिपोर्ट का संशोधित अंक है, में 12 अक्टूबर 2021 तक के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी एनडीसी को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है कि साल 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन साल 2010 की तुलना में 16 गुना ज्यादा होगा। कुल मिलाकर 2030 तक सारे एनडीसी का ग्रीनहाउस गैस-उत्सर्जन 54.9 गीगाटन होने का अनुमान लगाया है, जो इतनी ही कार्बन डाइऑसाइड की मात्रा के बराबर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे सारे एनडीसी मिलकर दुनिया का तापमान 2.7 डिग्री बढ़ा देंगे। संयुक्त राष्ट्र की विज्ञान शाखा, जलवायु-परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल यानी आईपीसीसी का निर्देश है कि इसी अवधि में उत्सर्जन का 45 फीसदी कम किया जाए। इसका मकसद वैश्विक तापमान की सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस तय करना और जलवायु परिवर्तन से होने वाले विनाशकारी दुष्प्रभावों को रोकना है। रिपोर्ट में यूएनएफसीसीसी को भेजे गए 116 एनडीसी का विश्लेषण किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि 2010 की तुलना में 2030 में नौ फीसद कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होगा।


E ZONE CARE

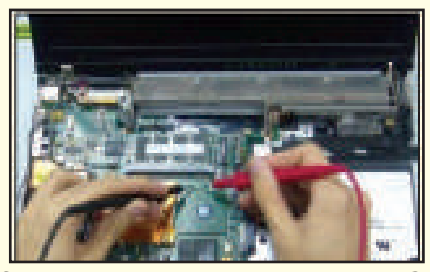

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED


# बढ़ने लगी कश्मीर में राजकीय पशु हंगुल की आबादी

**स्नेहा महाले**

***हंगुल, लाल हिरण की नस्ल, जम्मू-कश्मीर का राज्य पशु है। अब इस जीव की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। वर्ष 2019 में राज्य में कुल 237 हंगुल थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 261 हो गयी है। पालतू जानवरों के चरने की वजह और कश्मीर में तनाव से भी इस जीव के भोजन पर संकट रहा है। इनकी संख्या में चारागाह की कमी को एक महत्वपूर्ण वजह बताया जाता रहा है।इस जीव की संख्या पर निरंतर निगरानी से ही इसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। वैसे, इनपर सालभर निगरानी रखना काफी मुश्किल काम है।***

हंगुल या कश्मीरी हिरण की गिरती संख्या चिंता का सबब रहा है। पर मार्च 2021 में सामने आई संख्या उत्साहजनक है। वन्यजीव संरक्षण विभाग के अनुसार, लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हंगुल की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। साल 2019 में इस जीव की संख्या 237 थी। अब यह बढ़कर 261 हो गयी है। छः साल पहले यानी 2015 में ही इनकी संख्या बढ़ने लगी थी। तब इस कश्मीरी हिरण की कुल संख्या 186 थी।

वर्तमान जम्मू और कश्मीर के राज्य पशु, हंगुल की पहचान पहली बार 1844 में शोधकर्ता अल्फर्ड वैगनर ने की थी। माना जाता है कि यह जीव मध्य एशिया के बुखारा से कई देश होते हुए कश्मीर आया। ''वन अखरोट या कहें इंडियन हॉर्स चेस्टनट, हिरणों का पसंदीदा भोजन है। इसे स्थानीय भाषा में 'हान दून' कहते हैं। माना जाता है कि इसी आधार पर इस जीव का नाम हंगुल पड़ा। इसके अतिरिक्त, हंगुल घास, झाड़ियां, पत्ते भी खाते हैं। उन्नीसवीं सदी में, हंगुल उत्तरी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान में बहुतायत में पाए जाते थे। अब इनकी सीमा श्रीनगर के पास दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित है,'' भारत के लुप्तप्राय और वन्यजीवों पर एक वेबसाइट के संस्थापक और संपादक अतुल गुप्ता कहते हैं।

हंगुल मार्च में अपना सींग गिराकर पहाड़ के ऊंचाई वाले हिस्से का रुख करते हैं। अगस्त तक उनके सींग दोबारा उग आते हैं। सितंबर-अक्टूबर तक ये पुनः नीचे चले आते हैं। इसी समय कश्मीर में इन्हें देखा जा सकता है। यही समय होता है जब नर हंगुल, मादाओं को रिझाने का काम करते है। वे अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ते भी हैं ताकि मादा हंगुल को अपना वर्चस्व दिखा सकें।''हंगुल आम तौर पर 2-18 के समूहों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मादा को रिझाने के दौरान नर एक-दूसरे के प्रति असहिष्णु हो जाते हैं। लगभग आठ महीनों के बाद, मादा बच्चे को जन्म देती है जिसे फॉन कहते हैं। सामान्यतः एक ही बच्चा होता है पर कुछेक मामलों में जुड़वां बच्चे भी पैदा होते हैं। मादा हंगुल 16 महीने तक बच्चे के वयस्क होने तक देखभाल करती है,'' स्वतंत्र वन्यजीव शोधकर्ता और हंगुल संरक्षण के लिए काम करने वाले कश्मीर के अजय सिन्हा कहते हैं। सिन्हा इस जीव के गणना में भी शामिल थे।

### हंगुल की संख्या में गिरावट

उन्नीसवीं शताब्दी में, कश्मीर में लगभग 3,000 से 5,000 हंगुल पाए जाते थे। किशनगंगा के करेन से लेकर लोलाब घाटी में दोरुसा तक, और बांदीपोरा, तुलैल, बालटाल, अरु, त्राल और किश्तवाड़ में, हर जगह इन्हें देखा जा सकता था। लगातार शिकार के कारण उनकी संख्या में गिरावट आई है। कश्मीर के तत्कालीन महाराजा ने दाचीगाम में हंगुल के शिकार से जुड़ा एक खेल क्षेत्र भी घोषित किया जहां आमलोगों का प्रवेश वर्जित था। स्वतंत्रता के बाद, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण ने शिकार के खतरे को और कम कर दिया। हालांकि, कश्मीर में संघर्ष के कारण पशुओं के चरने और निवास स्थान का लगातार क्षरण हुआ। इससे एक नई चुनौती सामने आई। सिन्हा कहते हैं कि गर्मी के दिनों में हंगुल के चरने के लिए घाटी एक आदर्श बन जाया करती थी। सशस्त्र संघर्ष के बाद उनका दायरा सिमटा। घुमंतू चरवाहे भी अपने पशुओं को वहीं चराने लगे जहां हंगुल चरते थे। क्योंकि इनके चरवाही के क्षेत्र आसानी से आना-जाना संभव नहीं रहाउनकी घटती संख्या का एक और तत्कालीन कारण है नर और मादा हंगुल की संख्या के अनुपात में गिरावट।

### जनगणना कैसे मददगार

तेंदुए और हिमालयी भालू जैसे शिकारी जीवों के लिए हंगुल, भोजन हैं। ऊपरी स्थानों पर अधिकांश जानवर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में हंगुल का महत्व और बढ़ जाता है। फिलहाल, हंगुल संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू नर से मादा और फॉन से मादा अनुपात के असंतुलन को बहाल करना होगा। लेकिन यह करना मुश्किल है। हंगुल जंगल में मुश्किल से दिखता है, ऐसे में इनका अवलोकन कर आंकड़े इकट्ठा करना शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती है,'' गुप्ता कहते हैं। इसलिए हर दो साल में जनगणना कराना जरूरी हो जाता है। निरंतर और नियमित जनसंख्या निगरानी ही एकमात्र तरीका है जिससे शोधकर्ता और वैज्ञानिक एक ऐसी प्रजाति के बारे में सामान्य जानकारी पा सकें। गंभीर रूप से लुप्तप्राय हंगुल का संरक्षण एक मुश्किल काम है। उनतक पहुंचना एक चुनौती है। ताजा गणना वन विभाग के 350 कर्मचारी, विद्यार्थी और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई थी। वन्यजीव अधिकारियों ने मीडिया को बताया गया कि गणना की अंतिम रिपोर्ट से इस जीव के नर और मादा का अनुपात तथा इनकी आबादी कब तक जीवित रहेगी, आदि के बारे में विस्तृत पता चलेगा।

### संरक्षण का काम जारी

हंगुल के संरक्षण को लेकर बेहद जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। एक परियोजना के तहत शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने यू.एस. के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर संरक्षण प्रजनन, संरक्षण आनुवंशिकी और सामुदायिक विकास की दिशा में काम कर रही है। उनकी योजना जंगलों से हंगुल को पकड़कर इंसानी देखरेख में उनका प्रजनन कराया जाता है। गुप्ता कहते हैं, ''कई चुनौतियां हैं जिन्हें तत्काल ठीक करने की जरूरत है। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने की जरूरत है जो कि अक्सर हंगुल का शिकार करते हैं। बाघ के लिए बने गलियारों की तर्ज पर हंगुल गलियारा भी बनाया जा सकता है ताकि ये घास के मैदानों तक पहुंच सकें और स्वतंत्र रूप से चर सकें।

हंगुल कश्मीर का राज्य पशु रहा है और कुछ संकेत दिख रहे हैं कि जानवर अपने पहले के निवास स्थान पर लौट रहा है। पिछले साल मध्य कश्मीर के गांदरबल में लगभग 6 से 8 हिरणों का एक जंगली झुंड देखा गया था।

### कोई भी देश जलवायु परिवर्तन से नहीं बचेगा

एजेंसियां :यदि ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन को रोकने के लिए अभी तत्काल कार्रवाई न की गई तो लू, सूखा, समुद्र के बढ़ते जल स्तर, खाद्य आपूर्ति में आती कमी और पर्यटन पर बढ़ते खतरे से कोई भी देश नहीं बच पाएगा।

जलवायु में आ रहा बदलाव पहले ही जी20 देशों को प्रभावित कर रहा है। पिछले 20 वर्षों के दौरान सभी जी20 देशों में गर्मी से सम्बंधित मौतों में कम से कम 15 फीसदी की वृद्धि हुई है। जबकि जंगल में लगने वाली आग ने कनाडा से करीब डेढ़ गुना ज्यादा क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर से लेकर साफ पानी की घटती उपलब्धता और डेंगू के कहर से लेकर भीषण गर्मी के कारण होने वाली मौतों तक जीवन का कोई ऐसा कोई पहलु नहीं होगा जो जी20 देशों में जलवायु परिवर्तन से अछूता रह जाएगा।,एक रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि अगले 30 वर्षों के भीतर जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर असर डालेगा। ऐसे में रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए जी20 देशों को अपने उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की जरूरत है

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी )आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।